श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं आनरेबल मेम्बर को यही बताना चाहता हूँ कि 122 मिल्स कानपूर की भी शामिल हैं ।

SHRI PRAGADA KOTAIAH : Madam, by the end of March, the Government spent Rs. 11,035 crores for modernising the mills in the private sector as well as Hie public sector. I would like to know us to how many of them are actually working now and what are the number of mills, both in the private sector and the public sector, for which the modernisation fund has been given.

SHRI G. VENKAT SWAMY : The Government sanctioned Rs. 750 crores for modernisation programme and this was allotted to the mills in the private sector as well as in the public sector. A large number of mills have taken this loan. This fund was created in 1st August, 1986. This amount of Rs. 750 crores was disbursed by the Government of India through the IDBI. Altogether, a sum of Rs. 877.94 crores was disbursed for modernisation of the mills.

SHRI PRAGADA KOTAIAH : Madam, I wanted to know as to how many of them are actually working and how many of them are not working even after modernisation,

;

SHRI G. VENKAT SWAMY : As I mentioned, around Rs. 877 crores were allocated for modernisation of the textile mills and all the mills are operating now.

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे : मैडम, एन० टी० सी० में एक तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, बी० आई० एफ० आर० में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर हर स्टेट में स्टेट्स के कन्सर्न होते हैं । जब भी रिनोवेशन और माडर्नाइजेशन की स्कीम एप्रूव कर देते हैं तो ऐसा होता है कि एक बार माडर्नाइजेशन हो गया तो ये मालिक लोग कामर्शियलाइज करते है और कामर्शियलाइज करके वहां की जो प्रापर्टी है वह बेचने का उनका प्रयास होता है । सभी उसी तरह से फिर दिवाला निकालते हैं और फिर दुबारा वह प्रापर्टी या वह मिल लास में आती है । इसलिए क्या आपके पास ऐसी कोई मानीटरिंग एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की, एन० टी० सी० की और फाइनेंस की, इतना ही मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : ऐसी कोई स्कीम प्राइवेट सेक्टर के माडर्नाइजेशन के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में तो नहीं है । आलरेडी एन० टी० सी० मिल्स को हमने लिया है, जिसको ट्रिपारटाइट कमेटी ने एप्रूव किया । उसको हम कैबिनेट नोट बनाने के बाद टेक्सटाइल, एन० टी० सी० मिल्स के लिए जायेंगे । मगर प्रायवेट मिल्स के माडर्नाइजेशन के लिए जैसा मैंने कहा कि लास्ट टाइम 750 करोड़ रुपीज हमने रखा था । वह जो हुआ है उसमें वे सारी की सारी अच्छी चल रही है । रहा यह कि चंद लोग, प्रायवेट मिल ओनर्स–और असल क्वेश्चन हमारे शिन्दे जी का यही है कि वे माडर्नाइजेशन के नाम पर प्रापर्टीज को, सरप्लस लैंड को बेचकर फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में कोई कानून नहीं है । मगर स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले सकती है ।

Doordarshan Kendra at Bhubaneswar

*324. SHRI SARDA MOHANTY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bhubaneswar, the Capital of Orissa, is the only State Capital in the country having no Dooardarshan Kendra; and

(b) if so, by when Government of India porpose to instal Doordarshan Kendra at Bhubaneswar ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No, Sir. A Doordarshan Kendra is operating at Bhubaneswar Since 19-11-1992.

(b) Does not arise.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question your is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

यू० एन० ट्रस्ट फंड के लिए सहायता

*श्री राम गोपाल यादव :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एन० ट्रस्ट फंड के अध्यक्ष ने बेरोजगार युवाओं को काम देने हेतु केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता की मांग की है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आश्वासन दिया है ;